



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 147]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 11, 2014/ज्येष्ठ 21, 1936

No. 147]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 11, 2014/JYAISTHA 21, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2014

(निर्णायक समीक्षा)

विषय : चीन जन.गण. में उद्धवित अथवा वहां से निर्यातित विटामिन-सी के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत।

सं.15/10/2014-डीजीएडी.— समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम कहा गया है) और सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 (जिसे एतदपश्चात नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतदपश्चात प्राधिकारी कहा गया है) ने अपनी मूल जांच में चीन जन.गण. और जापान में उद्धवित अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर निर्णायक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने की सिफारिश करते हुए दिनांक 25 मई, 1998 की अपनी अधिसूचना सं. 10/1/97-एडीडी के तहत चीन जन.गण. और जापान में उद्धवित अथवा वहां से निर्यातित "विटामिन-सी" (जिसे एतदपश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर निर्णायक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने की सिफारिश की थी और केंद्रीय सरकार ने दिनांक 24 जुलाई, 1998 की अधिसूचना सं. 53/98-सीमाशुल्क के तहत निर्णायक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किया था।

2. और यतः, प्राधिकारी ने दिनांक 24 जुलाई, 1998 की अधिसूचना संख्या 53/98-सीमाशुल्क के तहत संबद्ध वस्तु के आयातों पर अधिरोपित अंतिम पाटनरोधी शुल्क के संबंध में एक निर्णायक समीक्षा जांच का आयोजन किया था और यह जांच की थी कि क्या पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने से पाटन और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के क्षति होने की संभावना है और चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क का दिनांक 31 जुलाई, 2003 की अधिसूचना सं.14/14/2992-डीजीएडी के तहत विस्तार करने की सिफारिश की थी। इस शुल्क को 25 अक्टूबर, 2003 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 159/2003-सीमाशुल्क के तहत बढ़ाया गया था।

3. यतः, प्राधिकारी ने द्वितीय निर्णायक समीक्षा जांच का आयोजन किया और दिनांक 29 मई, 2009 की अधिसूचना सं. 15/16/2008 के तहत पाटनरोधी शुल्क का विस्तार करने की सिफारिश की थी। केंद्रीय सरकार द्वारा दिनांक 16 जून, 2009 की अधिसूचना सं. 67/2009-सीमाशुल्क के तहत पाटनरोधी शुल्क पांच वर्षों के लिए बढ़ाया गया था।

4. यतः, सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क, यदि उसका पहले प्रतिसंहरण नहीं कर दिया जाता है तो ऐसे अधिरोपण की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति के पश्चात निष्प्रभावी हो जाएगा।

5. और, उपर्युक्त प्रावधान के होते हुए भी प्राधिकारी को, घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से इस साधन की समाप्ति की तारीख से पहले किसी युक्तियुक्त अवधि में किए गए विधिवत साक्ष्यांकित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करना अपेक्षित होता है कि क्या इस शुल्क को समाप्त कर देने से पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

समीक्षा के लिए अनुरोध

6. और, यतः, उपर्युक्त प्रावधानों के अंतर्गत बजाज हेल्थकेयर लिमिटेड (जिसे एतदपश्चात आवेदक कहा गया है) ने घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हुए, प्राधिकारी के समक्ष एक विधिवत साक्ष्यांकित आवेदनपत्र यह अनुरोध करते हुए दायर किया कि केंद्रीय सरकार द्वारा दिनांक 16 जून, 2009 की अधिसूचना सं. 67/2009 के तहत अधिरोपित प्रभावी पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता बनाई रखी जाए। यह अनुरोध इस आधार पर आधारित है कि चीन जन.गण. (जिसे एतदपश्चात संबद्ध देश कहा गया है) से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित होने के बावजूद पाटन जारी रहा है और घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से पाटन के कारण क्षति होती रही क्योंकि प्रभावी पाटनरोधी शुल्क का स्वरूप एवं उसकी प्रमाणा अपर्याप्त रही है। आवेदक ने पुनः यह तर्क दिया है कि संबद्ध देश के विरुद्ध इस साधन को समाप्त कर देने से घरेलू उद्योग को पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना बनी रहेगी। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि पाटनरोधी साधन का प्रतिसंहरण कर लिए जाने से घरेलू उद्योग को क्षति और अधिक बढ़ जाएगी और इसलिए इस शुल्क को अगले पांच वर्षों तक बनाए रखने की आवश्यकता है।

7. और, आवेदक द्वारा दिए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर प्राधिकारी यह विचार करते हैं कि संबद्ध देश में उद्भूत या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर प्रभावी पाटनरोधी शुल्क के संबंध में निर्णायक समीक्षा प्रक्रिया प्रारंभ करना यह जांच करने के लिए उपयुक्त होगा कि क्या पाटन को समाप्त करने के लिए शुल्क का अधिरोपण जारी रखना आवश्यक है और क्या यदि शुल्क को समाप्त कर दिया जाए या उसमें कुछ अंतर लाया जाए या दोनों कर दिया गया तो क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना बनी रहेगी।

घरेलू उद्योग एवं आधार

8. यह आवेदनपत्र भारत में संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादकों की ओर से बजाज हेल्थकेयर लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। इसके अतिरिक्त, अमोली आर्गनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और रैकन फार्मा केम प्राइवेट लिमिटेड ने इस याचिका का समर्थन किया है। अभिलेख में उपलब्ध जानकारी के अनुसार आवेदक का संबद्ध वस्तु के भारतीय उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा बनता है और इसलिए, वह पाटनरोधी नियमावली के आशय के अंतर्गत घरेलू उद्योग है और प्रमुख नियमावली के आशय के अंतर्गत आधार पर मानदंड को पूरा करता है।

जांच शुरूआत

9. घरेलू उद्योग द्वारा समीक्षा की आवश्यकता के लिए अपेक्षित प्रस्तुत सभी साक्ष्यांकित प्रथम दृष्टया सकारात्मक साक्ष्यों के आधार पर स्वयं संतुष्ट होकर प्राधिकारी संबद्ध देश में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर प्रभावी पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण की निरंतरता की जरूरत की समीक्षा करने और यह जानने के लिए कि क्या शुल्क को समाप्त कर देने से पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति बने रहने की संभावना है या नहीं, पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार निर्णायक समीक्षा एतद्वारा प्रारंभ करते हैं।

विचाराधीन उत्पाद

10. वर्तमान जांच में अंतर्गस्त विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण. में उद्भवित अथवा वहां से निर्यातित अपने सभी रूपों एवं अवकलजों में विटामिन-सी है। इसे एस्कार्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। इसे सीमाशुल्क अधिनियम के अंतर्गत सीमाशुल्क उपशीर्षक संख्या 29362700 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इसे अन्य समानार्थियों के रूप में जाना जाता है। एल-जाइलोएस्कार्बिन एसिड, 3-आक्सो एल-गुलोफरानोलैक्टोन (इनाल फार्म), एल-3-कीटोथियोहेक्नुरानिक एसिड लैक्टोन आदि जैसा कि उसे प्रविष्टि संख्या "मेर्क इंडेक्स का 876" के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, यह वर्गीकरण मात्र एक संकेतात्मक है और यह किसी भी रूप में वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

11. फार्मास्युटिकल कंपनियां विभिन्न दवाइयों का उत्पादन करने के लिए प्राथमिकतः इस उत्पाद का प्रयोग करते हैं। तथापि, इस उत्पाद का गैर-फार्मास्युटिकल उद्योग में भी भारी प्रयोग होता है। विटामिन-सी एक कार्बनिक रसायन होता है। वर्तमान जांच एक समीक्षा जांच होने के कारण इसमें विचाराधीन उत्पाद वही रहेगा जैसाकि उसे पिछली जांच में परिभाषित किया गया है। इस अवधि के दौरान इस उत्पाद में कोई भारी विकास नहीं हुआ है।

प्रक्रिया

12. यह जांच यह निर्धारित करेगी कि क्या पाटन को समाप्त करने के लिए शुल्क का सतत अधिरोपण आवश्यक है या नहीं और क्या शुल्क को समाप्त कर दिए जाने से या उसमें अंतर कर देने या दोनों से क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

- (i) इस समीक्षा में दिनांक 21 मई, 2009 की अधिसूचना संख्या 15/16/2008 के सभी पहलू शामिल होंगे।
- (ii) इस समीक्षा जांच में अंतर्गस्त देश चीन जन.गण. है।
- (iii) घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) अक्टूबर, 2012 से सितम्बर, 2013 है। यतः प्राधिकारी वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) अक्टूबर, 2012 से दिसम्बर, 2013 रखते हैं। तथापि क्षति जांच अवधि में अप्रैल, 10 - मार्च, 11, अप्रैल 11 - मार्च, 12, अप्रैल 12 - मार्च, 13 और जांच की अवधि शामिल होगी।
- (iv) प्रमुख नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, और 20 के प्रावधान इस समीक्षा में यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

13. सम्बद्ध देशों के निर्यातकों तथा उनकी सरकारों को भारसित स्थित उनके राजदूतावासों के जरिए और भारत में इस उत्पाद से संबंधित ज्ञात आयातकों तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित स्वरूप और ढंग से सभी संगत जानकारी प्रस्तुत करने और प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत करने के लिए अलग से संबोधित किया जा

रहा है:-

निर्दिष्ट प्राधिकारी

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

कमरा नं. 132, उद्योग भवन

नई दिल्ली-110011

14. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे उल्लिखित समय सीमा के अंदर विहित स्वरूप और ढंग से जांच से संगत सूचना प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुतिकरण करने वाले किसी अन्य पक्षकार को उसका अगोपनीय पाठ अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तुत करना भी अपेक्षित होगा।

समय-सीमा

15. वर्तमान जांच से संबंधित किसी सूचना को लिखित रूप में प्रेषित किया जाना चाहिए जिससे कि यह प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 (चालीस) दिनों से अनधिक समय में पहुँच जाए। यदि निर्धारित समय-सीमा के अंदर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं।

16. वर्तमान मामले में सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे अपने हित (हित की प्रकृति सहित) की सूचना दें तथा अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर करें और घरेलू उद्योग के आवेदनपत्र पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस (40) दिनों के अंदर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करें। यह सूचना हार्ड कापी और साफ्ट कापी दोनों रूपों में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

17. प्रश्नोत्तर प्रत्युत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष किसी प्रस्तुति (इससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) करने वाले पक्षकारों से इसे दो पृथक सेटों में यदि "गोपनीयता" का इसके किसी भाग पर दावा किया जाता है, फाइल किया जाना अपेक्षित है:-

- (क) एक सेट गोपनीय रूप में (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, अनुक्रमणिका, आदि सहित) चिन्हित किया गया हो, और
- (ख) एक अन्य सेट अगोपनीय के रूप में (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, अनुक्रमणिका, आदि सहित) चिन्हित किया गया हो।

18. "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" की प्रस्तुति को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" रूप में स्पष्टतः चिन्हित किया जाना चाहिए। ऐसे चिन्हांकन के बिना की गई प्रस्तुति प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय रूप में समझी जाएगी और प्राधिकारी इस बात के लिए स्वतंत्र होंगे कि ऐसी प्रस्तुति का निरीक्षण करने के लिए वह अन्य इच्छुक पक्षकारों को अनुमति प्रदान करे। दोनों संस्करणों की साफ्ट कापी भी प्रत्येक के पांच (5) सेटों में हार्ड कापी के साथ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा।

19. गोपनीय संस्करण में ऐसी सभी सूचनाएं समाविष्ट होंगी जो प्रकृति में गोपनीय हो और/अथवा अन्य सूचना जिसके बारे में ऐसी सूचना की आपूर्ति करने वाला गोपनीयता के रूप में दावा करता हो। सूचना जिसकी प्रकृति में गोपनीयता के रूप में दावा किया जाता है अथवा सूचना जिस पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, के लिए, सूचना आपूर्तिकर्ता से प्राप्त सूचना कि ऐसी सूचना क्यों प्रकट नहीं की जा सकती है, के साथ एक उचित कारण विवरण दिया जाना अपेक्षित है।

20. अगोपनीय संस्करण सूचना अनुक्रमित अथवा रिक्त किए गए (यदि अनुक्रमणिका सम्भव न हो) और जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया हो, के आधार पर सार रूप में की गई गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सार इतने विस्तृत रूप में हो कि उससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार की पर्याप्त समझ प्राप्त हो सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत करना संभव नहीं है और उसके कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि उसका सार प्रस्तुत करना संभव क्यों नहीं है।

21. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच करने के पश्चात गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए किया गया अनुरोध वांछित नहीं है अथवा सूचना का प्रदाता उस सूचना को सार्वजनिक करने का या तो इच्छुक नहीं है या उसका सामान्यीकृत अथवा सारांश रूप में प्रकटीकरण करने को प्राधिकृत करना नहीं चाहता है तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की अवहेलना कर सकते हैं।

22. सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना अथवा गोपनीयता की दावे के संबंध में सद्कारण के बिना किए गए किसी भी प्रस्तुतिकरण को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

23. प्रदान कराई गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लिए जाने पर प्राधिकारी ऐसी सूचना प्रदान कराने वाले पक्षकार द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किए बिना किसी भी पक्षकार को उस सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

24. प्राटनरोधी नियमावली के नियम 6 (7) के अनुरूप कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय पाठ युक्त सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

असहयोग

25. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार किसी सूचना की पहुंच तक मनाही करता है और युक्तिसंगत अवधि के अंदर आवश्यक सूचना प्रदान नहीं कराता है अथवा जांच में भारी व्यवधान उत्पन्न करता है तो प्राधिकारी उनको उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को समुचित सिफारिशें कर सकते हैं।

जे. के. दादू निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2014

(Sunset Review)

Subject: Initiation of Sunset Review investigation in respect of anti-dumping duty imposed on the imports of Vitamin-C originating in or exported from China PR.

No 15/10/2014-DGAD:- Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter also referred to as the AD Rules or Rules), the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) had in the original investigation, recommended imposition of definitive anti-dumping duty on the imports of "Vitamin-C" (hereinafter referred as the subject goods), originating in or exported from China PR and Japan vide Notification No. 10/1/97/ADD dated 25th May, 1998, recommending imposition of definitive anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from China PR and Japan, and definitive anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Notification No. 53/98-Cus dated 24th July, 1998.

2. WHEREAS, the Authority conducted a sunset review investigation in respect of the final anti-dumping duty imposed on the imports of the subject goods vide Notification No. 53/98-Cus dated 24th July, 1998 and examined whether cessation of anti-dumping duty was likely to lead to dumping and consequent injury to the domestic industry and recommended extension of anti-dumping duty imposed on the imports of the subject goods from China PR vide Notification No. 14/14/2002-DGAD dated 31st July, 2003. The duty was extended by the Central Government vide Customs Notification 159/2003-Customs dated 24th October, 2003.

3. WHEREAS, the Authority conducted second sunset review investigation and recommended extension of anti dumping duty vide Notification No. 15/16/2008 dated 21st May, 2009. The anti-dumping duties were extended by the Central Government for five years vide Notification No. 67/2009-Customs dated 16th June, 2009.

4. WHEREAS, in terms of the Customs Tariff Act, the antidumping duty imposed shall unless revoked earlier cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition.

5. AND, notwithstanding the above provision, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the date of the expiry of the measure as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

Request for Review

6. AND, WEHERAS, in terms of the above provisions, Bajaj Healthcare Limited (hereinafter referred to as the

applicant) representing the Domestic Industry has approached the Authority with a duly substantiated application requesting for continuation of the antidumping duties in force imposed by the Central Government vide Notification No. 67/2009-customs dated 16th June, 2009. The request is based on the grounds that dumping has continued in spite of imposition of antidumping duty on the import of the subject goods from China PR (hereinafter referred as the subject country) and the domestic industry continues to suffer injury on account of dumping from the subject country as the form and quantum of anti dumping duty in force has been insufficient. The applicant has further argued that expiry of the measure against the subject country would be likely to result in continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. The applicant also claims that revocation of anti-dumping measures would result in intensified injury to the domestic industry and, therefore, the duty is required to be continued for a further period of five years.

7. AND, the Authority on the basis of prime facie evidence given by the applicant considers that initiation of sunset review proceedings in respect of the anti dumping duty in force on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country would be appropriate to examine the need for continued imposition of such duties to offset dumping and whether the injury would be likely to continue or recur if the duties were removed or varied or both.

Domestic Industry and Standing

8. The application has been filed by Bajaj Healthcare Limited on behalf of the domestic producers of the subject goods in India. Further, Amoli Organics Pvt. Ltd. and Reckon Pharmachem Pvt. Ltd have supported the petition. As per the information available on record, the applicant accounts for a major proportion in Indian production of the subject goods and, therefore, constitutes the domestic industry within the meaning of the AD Rules and also satisfies the criteria of standing in terms of the Rules.

Initiation

9. Having satisfied itself on the basis of positive prima facie evidence of dumping and injury to the domestic industry given by the applicant, substantiating the need for a review, the Authority hereby initiates the Sunset Review in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23 of Antidumping Rules, to review the need for continued imposition of duties in force on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country and whether the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

Product under consideration

10. The product under consideration involved in the present investigation is Vitamin- C in all its form and derivatives, originating in or exported from China PR. It is also known as ascorbic acid. It is classified under customs sub-heading no. 29362700 under the Customs Tariff Act. It is also known by various synonyms such as L-Xyloascorbic Acid, 3-Oxo L-Gulofuranolactone (enol form), L-3-Ketothreohexuronic Acid Lactone etc., as described under entry number '867 of Merck Index'. The classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

11. The pharmaceuticals companies for production of various medicines primarily use Vitamin-C. However, the product has significant uses in non-pharmaceutical industry also. Vitamin-C is an organic chemical. Present investigation being a review investigation, product under consideration remains the same as has been defined in the previous investigations. There has been no significant development in the product over the period.

Procedure

12. The investigation will determine as to whether the continued imposition of the duties is necessary to offset dumping and whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both.

- i. The review will cover all aspects of Notification No. 15/16/2008 dated 21st May, 2009.
- ii. The country involved in this review investigation is China PR.
- iii. The period of investigation (POI) for the purpose of the present review proposed by the domestic industry was from October, 2012 to September, 2013. However, the Authority determines October, 2012 to December, 2013 as the period of investigation (POI) for the purpose of the present review. The injury investigation period will, however, cover the periods Apr'10-Mar'11, Apr'11-Mar'12, Apr'12-Mar'13 and the POI.
- iv. The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

Submission of Information

13. The exporters in the subject country, its government through its Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties

Ministry of Commerce and Industry
Department of Commerce
Room No 132, Udyog Bhavan, New Delhi-110011

14. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time Limit

15. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

16. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application within forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. The information must be submitted in hard copies as well as soft copies.

Submission of information on confidential basis

17. The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:-

- (a) one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and
- (b) the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).

18. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in five (5) sets of each.

19. The confidential version shall contain all information which are by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information can not be disclosed.

20. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

21. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

22. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

23. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

24. In terms of Rule 6(7) of the AD Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

25. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

J K Dadoo, Designated Authority